भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 893

जिसका उत्तर 23.07.2026 को दिया जाना है

सार्वजनिक परिवहन का विस्तार

893. श्रीमती साजदा अहमद:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर के शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन क्षमता में कमी का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मितव्ययिता उपायों और बजटीय बाधाओं ने सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के विस्तार और रखरखाव को प्रभावित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधियों का पश्चिम बंगाल सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) किफायती और कुशल सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) शहरी परिवहन शहरी नियोजन का एक भाग है, जो राज्य का विषय है। अतः, संबंधित राज्य सरकारें शहरी परिवहन प्रणाली की आयोजना, क्रियान्वयन और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हैं, जिसमें वित्तीय नियोजन और सार्वजनिक परिवहन क्षमता में कमी का आकलन शामिल है। भारत सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शहरी परिवहन प्रणालियों की योजना और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 2006, मेट्रो रेल नीति 2017, पारगमन उन्मुख विकास (टीओडी) नीति 2017 और अन्य नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

अभी तक, लगभग 1,159 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क चालू है, जिसमें दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का 82.15 किलोमीटर भाग शामिल है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई केंद्रीय वित्तीय सहायता का विवरण नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

वित्तीय वर्ष	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27
बजट	₹23,102.2	₹28,543.86	₹29,451.00 करोड़	₹30,942.05 करोड़ (बजट

	करोड़ (वास्तविक)	करोड़ (वास्तविक)	(वास्तविक)	अनुमान)

पीएम-ईबस सेवा योजना के तहत भागीदार 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित और प्रयुक्त कुल धनराशि का विवरण अनुलग्नक में संलग्न है। पश्चिम बंगाल राज्य ने पीएम-ईबस सेवा योजना में भाग नहीं लिया है।

(घ) वर्ष 2024 से अब तक लगभग 383 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क के लिए 1,59,109.56 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत देश में सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना में सुधार के लिए 116 शहरों में 10,000 बसों को मंजूरी दे दी गई है।

अनुलग्नक

'सार्वजनिक परिवहन का विस्तार' के संबंध में श्रीमती साजदा अहमद के द्वारा दिनांक 23.07.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 893 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क्र.सं.	राज्य का नाम / संघ राज्य क्षेत्र	बीटीएम* स्वीकृत राशि।(करोड़ रुपये में)	सिविल स्वीकृत राशि(करोड़ रुपये में)	कुल स्वीकृत राशि(करोड़ रुपये में)	बीटीएम जारी (करोड़ रुपये में)	सिविल जारी (करोड़ रुपये में)	कुल जारी(करोड़ रुपये में)
1.	आंध्र प्रदेश	79.98	65.41	145.39	44.70	0.00	44.70
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	3.84	12.81	16.65	3.83	8.00	11.83
4.	बिहार	79.25	33.21	112.46	79.25	8.30	87.55
5.	छत्तीसगढ़	30.36	20.19	50.55	21.16	3.28	24.44
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	35.69	40.61	76.30	10.75	6.11	16.86
8.	हरियाणा	13.44	8.69	22.13	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	14.28	28.09	42.37	0.00	0.00	0.00
11।	कर्नाटक	46.18	59.82	106.00	11.35	0.00	11.35
12.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	मध्य प्रदेश	55.66	41.77	97.43	30.56	4.58	35.14
14.	महाराष्ट्र	231.61	142.36	373.97	150.65	39.18	189.83
15.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मेघालय	8.95	9.00	17.95	8.95	4.50	13.45
17.	ओडिशा	54.11	34.05	88.16	33.53	9.36	42.89
18.	पुदुचेरी	8.15	9.55	17.70	8.15	0.00	8.15
19.	पंजाब	22.90	20.87	43.77	6.50	1.94	8.44
20.	राजस्थान	60.08	42.03	102.11	48.52	23.64	72.16
21.	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	उत्तराखंड	12.02	15.36	27.38	12.02	1.98	14.00
23.	चंडीगढ़	11.87	0.00	11.87	11.87	0.00	11.87
24.	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**768.37**	**583.82**	**1352.19**	**481.79**	**110.87**	**592.66**

* बिहाइंड-द-मीटर (बीटीएम)

****